RNI No.: DEL/BIL/2004/14598

Youngster

YOUNGSTER · ESTABLISHED 2004 · NEW DELHI · NOVEMBER 2020 · PAGES 4 · PRICE 1/- · MONTHLY BILINGUAL (HIN./ENG.)

सभ्य समाज के लिए नासूर के समान हैं नारी हिंसा और उत्पीड़न की घटनाएँ

भारत ही नहीं, दुनियाभर की महिलाओं पर बढ़ती हिंसा, शोषण, असुरक्षा एवं उत्पीड़न की घटनाएं एक गंभीर समस्या है। इस दिन महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने के और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता को रेखांकित करने वाले अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। महिलाओं के समूह व संगठन महिलाओं की समाज में चिंताजनक स्थिति और इसके परिणामस्वरूप, महिलाओं के शारीरिक, मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को सामने लाने के लिए विविध उपक्रम किये जाते हैं।

25 नवम्बर, 1960, को राजनैतिक कार्यकर्ता डोमिनिकन शासक राफेल ट्रुजिलो (1930–1961) के आदेश पर तीन बहनों– पैट्रिया मर्सिडीज मिराबेल, मारिया अर्जेंटीना मिनेर्वा मिराबैल तथा एंटोनिया मारिया टेरेसा मिराबैल की 1960 में क्रूरता से हत्या कर दी थी। इन तीनों बहनों ने ट्रुजिलो की तानाशाही का कड़ा विरोध किया था। महिला अधिकारों के समर्थक व कार्यकर्ता वर्ष 1981 से इस दिन को इन तीनों बहनों की मृत्यु की स्मृति के रूप में मनाते हैं। 17 दिसंबर 1999 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एकमत से यह निर्णय लिया गया कि 25 नवम्बर को महिलाओं के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

देश एवं दुनिया में विकास के साथ–साथ महिलाओं के प्रति हिंसक सोच थमने की बजाय नये–नये रूपों में सामने आती रही है। इसी हिंसक सामाजिक सोच एवं विचारधारा पर काबू पाने के लिये अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा–उन्मूलन दिवस महिलाओं के अस्तित्व एवं अस्मिता से जुड़ा एक ऐसा दिवस है जो दायित्वबोध की चेतना का संदेश देता है, महिलाओं के प्रति एक नयी सभ्य एवं शालीन सोच विकसित करने का आह्वान करता है। यह दिवस उन चौराहों पर पहरा देता है जहां से जीवन आदर्शों के भटकाव एवं नारी–हिंसा की संभावनाएं हैं, यह उन आकांक्षाओं को थामता है जिनकी हिंसक गति तो बहुत तेज होती है पर जो बिना उद्देश्य समाज की बेतहाशा दौड़ को दर्शाती है। इस दिवस को मनाने के उद्देश्यों में महिलाओं के प्रति बढ़ रही हिंसा को नियंत्रित करने का संकल्प भी है। यह दिवस नारी को शक्तिशाली, प्रगतिशील और संस्कारी बनाने का अनूठा माध्यम है।

अनुमान है कि दुनिया भर में 35 प्रतिशत महिलाओं ने शारीरिक और यौन हिंसा का अनुभव किसी नॉन–पार्टनर द्वारा अपने जीवन में किसी बिंदु पर किया है। हालांकि, कुछ राष्ट्रीय अध्ययनों से पता चलता है कि 70 प्रतिशत महिलाओं ने अपने जीवनकाल में एक अंतरंग साथी से शारीरिक और यौन हिंसा का अनुभव किया है। दुनियाभर में पाए गए सभी मानव तस्करी के पीड़ितों में से 51 प्रतिशत वयस्क महिलाओं का खाता है। यूरोपीय संघ की रिपोर्ट में 10 महिलाओं में से एक ने 15 साल की उम्र से साइबर–उत्पीड़न का अनुभव किया है। 18 से 29 वर्ष की आयु के बीच युवा महिलाओं में जोखिम सबसे अधिक है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक वैश्विक महामारी है। 70 प्रतिशत महिलाओं की संख्या अपने जीवनकाल में हिंसा का अनुभव करती है। भारत के राजस्थान प्रांत में तो कन्या–शिशुओं को जन्म लेते ही मान देने की भयावह मानसिकता रही है। कुछ चिंतन और मनन करने से हमें पता चलता है कि महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न, फब्तियां कसने, छेड़खानी, वैश्यावृत्ति, गर्भाधारण के लिए विवश करना, महिलाओं और लड़कियों को खरीदना और बेचना, युद्ध से उत्पन्न हिंसक व्यवहार और जेलों में भीषण यातनाओं का क्रम अभी भी महिलाओं के विरुद्ध जारी है और इसमें कमी होने के बजाए वृद्धि हो रही है।

आज हिंसा एवं उत्पीड़न से ग्रस्त समाज की महिलाओं पर विमर्श जरूरी है। विकसित एवं विकासशील देशों में महिलाओं पर अत्याचार, शोषण, भेदभाव एवं उत्पीड़न का साया छाया रहता है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत सहित दुनियाभर में अल्पसंख्यक और संबंधित देशों के मूल समुदाय की महिलाएं अपनी जाति, धर्म और मूल पहचान के कारण बलात्कार, छेड़छाड़, उत्पीड़न और हत्या का शिकार होती हैं। माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप इंटरनेशनल ने 'दुनिया के अल्पसंख्यकों और मूल लोगों की दशा' नामक अपनी सालाना रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे दुनियाभर में अल्पसंख्यक और मूल समुदाय की महिलाएं हिंसा का शिकार ज्यादा होती हैं, चाहे वह संघर्ष का दौर हो या शांति का दौर। इस संगठन के कार्यकारी निदेशक मार्क लैटिमर ने कहा कि दुनियाभर में अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव के तहत महिलाओं को शारीरिक हिंसा का दंश झेलना पड़ता है। यह स्थिति भारत के सन्दर्भ में भी भयावह है।

भले ही भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्तमान में महिला सशक्तिकरण के लिए सराहनीय कार्य कर रही है बावजूद इसके आधुनिक युग में हजारों अल्पसंख्यक ही नहीं आम महिलाएं अपने अधिकारों से कोसों दूर हैं। सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए भले ही सैकड़ों योजनाएं तैयार की हों, परंतु महिला वर्ग में शिक्षा व जागरूकता की कमी आज भी खल रही है। अपने कर्तव्यों तथा अधिकारों से बेखबर महिलाओं की दुनिया को चूल्हे चौके तक ही सीमित रखा है। भारत में आदिवासी समुदाय की महिलाएं अपने अधिकारों से बेखबर हैं और उनका जीवन आज भी एक त्रासदी की तरह है।

आम महिलाओं और युवतियों की ही भांति अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं पर भी कहीं एसिड अटैक हो रहे हैं, तो कहीं निरंतर हत्याएं–बलात्कार हो रहे और कहीं तलाश–दहेज उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं। इन घटनाओं पर कभी–कभार शोर भी होता है, लोग विरोध प्रकट करते हैं, मीडिया सक्रिय होता है पर अपराध कम होने का नाम नहीं लेते क्यों। हम देख रहे हैं कि एक ओर भारतीय नेतृत्व में इच्छाशक्ति बढ़ी है लेकिन विडम्बना तो यह है कि आम नागरिकों में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को लेकर कोई बहुत आक्रोश या इस स्थिति में बदलाव की चाहत भी नहीं है। वे स्वाभाव से ही पुरुष वर्चस्व के पक्षधर और सामंती मनःस्थिति के कायल हैं। तब इस समस्या का समाधान कैसे सम्भव है?

हमारे देश–समाज में स्त्रियों का यौन उत्पीड़न लगातार जारी है लेकिन यह विडम्बना ही कही जायेगी कि सरकार, प्रशासन, न्यायालय, समाज और सामाजिक संस्थाओं के साथ मीडिया एवं सख्त कानून बन जाने पर भी इस कुकृत्य में कमी लाने में सफल नहीं हो पाये हैं। देश के हर कोने से महिलाओं के साथ दुष्कर्म, यौन प्रताड़ना, दहेज के लिये जलाया जाना, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना और स्त्रियों की खरीद–फरोख्त के समाचार सुनने को मिलते रहते हैं। महिलाओं को अल्पसंख्यक दायरे में लाने मात्र से उन पर हो रहे अत्याचारों पर नियंत्रण नहीं हो सकता। क्योंकि नारी उत्पीड़न, नारी तिरस्कार तथा नारी को निचले व निम्न दर्जे का समझने की जड़ हमारे प्राचीन धर्मशास्त्रों, हमारे रीति–रिवाजों, संस्कारों तथा धार्मिक ग्रंथों व धर्म सम्बंधी कथाओं में पायी जाती हैं।

नारी को छोटा व दोयम दर्जा का समझने की मानसिकता भारतीय समाज की रग–रग में समा चुकी है। असल प्रश्न इसी मानसिकता को बदलने का है। इन वर्षों में अपराध को छुपाने और अपराधी से डरने की प्रवृत्ति खत्म होने लगी है। वे चाहे मीटू जैसे आन्दोलनों से हो या निर्भया कांड के बाद बने कानूनों से। इसलिए ऐसे अपराध पूरे न सही लेकिन फिर भी काफी सामने आने लगे हैं। अन्यायी तब तक अन्याय करता है, जब तक कि उसे सहा जाये। महिलाओं में इस धारणा को पैदा करने के लिये न्याय प्रणाली और मानसिकता में मौलिक बदलाव की भी जरूरत है। देश में लोगों को महिलाओं के अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है और इसका पालन पूरी गंभीरता और इच्छाशक्ति से नहीं होता है। महिला सशक्तीकरण के तमाम दावों के बाद भी महिलाएँ अपने असल अधिकार से कोसों दूर हैं। उन्हें इस बात को समझना होगा कि दुर्घटना व्यक्ति और वक्त का चुनाव नहीं करती है और यह सब कुछ होने में उनका कोई दोष नहीं है।

पुरुष–समाज के प्रदूषित एवं विकृत हो चुके तौर–तरीके ही नहीं बदलने हैं बल्कि उन कारणों की जड़ों को भी उखाड़ फेंकना है जिनके कारण से बार–बार नारी को जहर के घूंट पीने को विवश होना पड़ता है। विश्व महिला हिंसा–उन्मूलन दिवस गैर–सरकारी संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सरकारों के लिए महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के प्रति जन–जागरूकता फैलाने का अवसर होता है। दुनिया को महिलाओं की मानवीय प्रतिष्ठा के वास्तविक सम्मान के लिए भूमिका प्रशस्त करना चाहिए ताकि उनके वास्तविक अधिकारों को दिलाने का काम व्यावहारिक हो सके। ताकि इस सृष्टि में बलात्कार, गैंगरेप, नारी उत्पीड़न, नारी–हिंसा जैसे शब्दों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए।

रूचिका रावन

अबकी बार, तीन सौ पार (व्यंग्य)

नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही,
नहीं विसाल मयस्सर तो आरजू ही सही

जी नहीं ये किसी हारे या हताश राजनैतिक पार्टी के कार्यकर्ता की पीड़ा या उन्माद नहीं है।बल्कि हाल के दिनों में तीन सौ शब्द काफी चर्चा में रहा। एक राजनैतिक दल ने तीन सौ की हुंकार के साथ चुनाव में हुंकार भरी और फिर अब वो समय पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं, धुंधली या पक्की ये तो इतिहास ही तय करेगा। तीन सौ की संख्या ने एक बार अमीरी का हब बनते जा रहे इस देश के बारे में आश्चर्यजनक आंकड़े पेश किये हैं कि इस देश में वेतनभोगी वर्ग की में सत्तर फीसदी लोगों की मासिक आमदनी दस हजार रूपये से कम है यानी करीब करीब तीन सौ रुपयों के आस पास। दिल्ली के उच्च शिक्षा संस्थान की रिहाइश की फीस तीन सौ रूपये होने पर मीडिया में खूब हल्ला मचा तबसे लोग दिल्ली और झुमरीतलैया के मुद्रा स्फीति का आगणन कर रहे हैं।

बशीर बद्र साहब के शेर की बड़ी मशहूर लाइन है

लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में

फिर तीन सौ पार की रार सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि अपने पड़ोस पाकिस्तान में टमाटर की बढ़ती कीमतों की हुंकार है, बाजार के विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि पाकिस्तान में रूपये ग्राफ गिरता जा रहा है जबकि टमाटर का श्राप बढ़ता जा रहा है। हाल ही में एक खबर ने काफी सुर्खियां बटोरी जब पाकिस्तान की नायला इनायत नामक युवती ने अपनी शादी में जेवरात की जगह टमाटर पहने। सारे साज श्रृंगार टमाटर से लदे फंदे थे... दुल्हन के सौंदर्य की लाली की तुलना टमाटर से करने वाले लोग तब पशोपेश में पड़ गए जब टमाटर जैसी उपमा के बजाय उन्हें साक्षात टमाटर ही नजर आये, दुल्हन ने बताया कि उसके वालिद ने दूल्हे को तीन पेटी टमाटर भी दिए हैं दहेज में। सुना है हाफिज सईद ने अपने जंगजू भेजे हैं कि कश्मीर के नाम पर कुछ टमाटर उस दूल्हे से सहयोग में मांगे हैं। हिंदुस्तान में तो दहेज लेना और देना प्रतिबंधित है लेकिन पाकिस्तान में दहेज खूब चलता है। वस्तुतः जो चीज हिंदुस्तान में प्रतिबंधित हो जाती है पाकिस्तान उसे सर माथे पर चढ़ा लेता है। अब जैसे खालिस्तान की मांग भारत में प्रतिबंधित है तो पाकिस्तान ने सबसे पहले भिंडरवाले का शिगूफा करतारपुर साहिब में छोड़ दिया ।वैष्णो देवी की यात्रा में सिद्धू की इतनी हूटिंग हुई थी कि वो पानी पानी हो गए थे, जिस सिद्धू को टीवी चौनल वालों ने निकाल दिया। पाकिस्तान ने सर माथे पर उसको बिठाया और तालिबान खान उर्फ इमरान खान नियाजी की कसीदे गढ़ने के लिए करतार पुर साहब में उसको बुला लिया। उसने अपनी बेसुरी राग लंतरानी मुसलसल चालू रखी जिसे वो सिद्धूइज्म कहते हैं लेकिन सिद्धू की सिद्धि अब फुस्स हो गयी वो पैविलियन में हिट विकेट होकर बैठे हैं।

उस्ताद अदीब इब्न ए सफी साहब ने आगाह किया था कि पाकिस्तानियों की बात का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए

अब कल तक पाकिस्तान आर्मी की विष कन्या माने जानी वाली राबी पीरजादा ने जहरीले सांप से कटवाने, अजगर और घड़ियाल से निगलवाने की धमकी भारतीय नेतृत्व को वो दे रही थीं अगर कश्मीर से 370 नहीं हटाया तो, लेकिन उन्हें क्या इल्म था कि जुल्म की जहराब पर पला बढ़ा विश्वासघात का बिच्छु उनको ही डंक मार जायेगा।

अदाकार और गुलूकार जब नफरत की अंधी गलियों में जाकर कुत्सित योजनाओं का हिस्सा बनते हैं तब अंजाम यही होता है, कल तक जिस राबी पीरजादा की सुरीली आवाज इंटरनेट पर कूक रही थी, आज पाकिस्तान के कुछ नालायक लोगों की वजह से उस गुलकारा की अश्लील वीडियोज समाज में गंदगी फैलाने की बायस बन रहे हैं, उस पर तुर्रा ये है कि कल तक खुलेआम धमकियां देने वाली, खुद चरमपंथियों की धमकी से डरी डरी है और बिलख बिलख कर माफी मांग रही है और अपनी जान की अमान भी—

किससे कहें कि छत की मुंडेरों से गिर पड़े
हमने ही तो ये पतंग उड़ायी थी शौकिया

अब तो डिप्लोमेसी का आलम ये हो गया है कि जो काम बंदूक से निकली गोली नहीं कर पाती वो काम पड़ोसी मुल्क के सब्जी की खाली होती झोली कर देती है। भारत के टमाटरों ने पाकिस्तान ना जाकर वो तबाही मचायी कि तौबा तौबा पूछिये मत। पाकिस्तान भारत की मिसाइलों के मुकाबले गौरी और गजनवी मिसाइलें तो बना सकता है तो मगर टमाटर पैदा नहीं कर सकता।

यही हाल दूसरे पड़ोसी बांग्लादेश का भी है, भले ही अपने अवैध नागरिकों को वो हमसे स्थल मार्ग से भी लेने को तैयार नहीं मगर भारत का प्याज उसने आनन फानन में हवाई मार्ग से मंगा लिया। भारत जब उन्हें अवैध घुसपैठिये सौंपता है तब तो वो उन्हें वापस लेने में दुनियाभर की आनाकानी करते हैं और 1971 का संधिपत्र खोजने लगते हैं, लेकिन भारत को ये उलाहना देने से बाज नहीं आते कि उसने बिना बताए प्याज की अचानक डिलीवरी रोक दी। इन बांग्लादेशियों का रवैया भी राजधानी के एक उच्च शिक्षा संस्थान के कुछ भटके हुए नौजवानों जैसा है जिन्हें छः लाख पंचानबे हजार की प्रति विद्यार्थी की सब्सिडी कम पड़ रही है।

ख्खुद को लोकतंत्र का सजग प्रहरी कहने वालों को काश ये पता होता कि प्रति बीघे पराली जलाने के लिये सौ रूपये की सब्सिडी जुटाने को सरकार प्रयासरत है। जहाँ कभी लाइट नहीं जाती उन्हें क्या पता कि मिट्टी के तेल की सब्सिडी बहुत कम हो गयी है जिससे इस देश के तमाम बच्चों के पढ़ने की अवधि कम हो गयी है। देश ने इन होनहारों को बड़ी उम्मीद से पढ़ने के लिये भेजा है, गुरुओं, शिक्षिकाओ से तू तू, मैं मैं, झुमा झटकी करने के लिये नहीं। सिर्फ लेनिन और चे—ग्वारा ही नहीं अपने लोगों की भी इज्जत करना सीखें।

एक उस्ताद शायर ने शाद फरमाया है कि

तस्वीरें तो घर में सजा लीं
टौर मुसव्विर दर दर हैं,
फन की इज्जत करने वालों कद्र
करो फनकारों की

समय का फेर है कि ममता बनर्जी ने हैदराबाद के एक फायरब्रांड नेता और खुद को कौम विशेष का ही खिदमतगार कहने वाले नेता पर अल्पसंख्यक तुष्टि करण का आरोप लगाया है, ये बात सच है, चुनाव पूर्व हुए गठबंधन की कसम।

अतिश कुमार

नए साल पर इन जगहों पर घूमें, बजट भी नहीं बिगड़ेगा

नए साल का स्वागत करने के लिए अधिकतर लोग घूमने का प्लान बनाते हैं। लेकिन साथ ही उनके मन में यह भी होता है कि नए साल का स्वागत करने के चक्कर में कहीं उनका बजट ना बिगड़ जाए। कई बार तो लोग इस वजह से अपने घूमने का प्लान भी कैंसिल कर देते हैं। अगर आपको भी लगता है कि नए साल में घूमने पर आपका बजट बिगड़ जाएगा तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको ऐसी कुछ जगहों के बारे में बता रहे हैं, जहां आप बजट में रहते हुए नए साल का स्वागत कर सकते हैं

गोवा

नए साल पर घूमने की बात हो और गोवा का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वैसे तो आप गोवा कभी भी घूमने जा सकते हैं, लेकिन नए साल का जश्न गोवा में एक बेहद ही अलग तरह से मनाया जाता है। अगर आप यहां गए हैं तो बोहेमियन बीच पार्टी से लेकर नाइट क्लब इवेंट्स में जाएं। दिसंबर के आखिरी दिनों में गोवा में पार्टी का दौर चालू रहता है, ऐसे में आप यहां जमकर मस्ती कर सकते हैं। अगर आप गोवा में न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने का मन बना रहे हैं, तो टीटो क्लब, मैम्बो कैफे व बोट क्रूज पार्टी को एन्जॉय करें। अगर आप पहले से ही पैकेज बुक करवाते हैं तो आपको हर व्यक्ति का लगभग पांच से सात हजार रूपए खर्च आएगा।

ऊटी

अगर आप शोर—शराबे से दूर एक शांत जगह पर रहकर नए साल का स्वागत करना चाहते हैं तो आपको ऊटी जाना चाहिए। आप यहां पर आकर टी फैक्टी और म्यूजियम, बोटिंग, बोटेनिकल गार्डन में जाएं। साथ ही नए साल की फील लेने के लिए आप सड़कों पर निकल जाएं। वहां पर आतिशबाजी का माहौल देखकर आपके मन को यकीनन काफी अच्छा लगेगा। अगर आप यहां जा रहे हैं तो आपका खर्च सात से आठ हजार रूपए प्रति व्यक्ति आएगा।

पांडिचेरी

समुद्र तटों पर बाइक चलाने से लेकर छत पर बने कैफे में घूमने तक पॉन्डिचेरी आपको नए साल में एक अलग ही अनुभव महसूस कराएगा। खासतौर से, अगर आपका बजट काफी कम है और आप किसी बेहतरीन जगह पर घूमना चाहते हैं तो पांडिचेरी यकीनन आपकी जरूरत को पूरा करेगा। अगर आप वहां जा रहे हैं तो श्री अरबिंदो आश्रम, प्रोमेनेड बीच, हेरिटेज वॉक, विइट फ्रेंच कॉलोनी जाएं। यहां पर आपका प्रति व्यक्ति खर्च लगभग चार से पांच हजार आएगा।

सुरभि

THIS MONTH

November 6, 1917 - During World War I, the Third Battle of Ypres concluded after five months as Canadian and Australian troops took Passchendaele. Their advance, measuring five miles, cost at least 240,000 soldiers.

*****

November 5, 1911 - Aviator C.P. Snow completed the first transcontinental flight across America, landing at Pasadena, California. He had taken off from Sheepshead Bay, New York, on September 17th and flew a distance of 3,417 miles.

*****

November 4, 1956 - Soviet Russian troops moved in to crush an uprising in Hungary.

*****

November 6, 1962 - The U.N. General Assembly adopted a resolution condemning South Africa for its apartheid policies and recommended economic sanctions.

*****

November 4, 1979 - About 500 young Iranian militants stormed the U.S. Embassy in Teheran, Iran, and took 90 hostages, including 52 Americans that they held captive for 444 days.

*****

November 4, 1995 - Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin was assassinated as he left a peace rally in Tel Aviv.

*****

Compilation:
Honey Shah

BASICS OF MEDIA

Electronic Cinema: A high-definition television camera that has a frame rate of 24 frames per second, which is identical to the frame rate of a film camera. Most electronic cinema cameras use high-quality, state-of-the-art lenses and high-definition viewfinders.

*****

Eng/efp Cameras And Camcorders : High-quality portable field production cameras. When the camera is docked with a VTR or other recording device, or has the recording device built into it, it is called a camcorder.

*****

Gain: Electronic amplification of the video signal, boosting primarily picture brightness.

*****

House Number: The in-house system of identification for each piece of recorded program material. Called the house number because the code numbers differ from station to station (house to house).

*****

Moiré Effect: Color vibrations that occur when narrow, contrasting stripes of a design interfere with the scanning lines of the television system.

*****

To Be Continued In Next Issue-

Compilation:
Rahul Mittal

संपादक की कलम से

प्रदूषण नियंत्रण का दिखावा

दिल्ली के साथ–साथ देश के एक बड़े हिस्से में वायु प्रदूषण के कहर के बीच सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सक्रियता दिखाई। इसी के साथ केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार भी अपने स्तर पर कुछ न कुछ करती हुई दिखाई दीं, लेकिन शायद नतीजा ढाक के तीन पात वाला ही रहने वाला है। इसका प्रमाण यह है कि दिल्ली और उसके आसपास हवा की गुणवत्ता और खराब होती दिखी। इसका सीधा मतलब है कि सेहत के लिए घातक साबित होते प्रदूषण से बचने के लिए ठोस उपाय नहीं किए जा रहे हैं। इसका पता इससे भी चलता है कि तमाम डांट–फटकार के बाद भी पंजाब में पराली दहन पर प्रभावी रोक नहीं लग सकी है। यदि हमारे नीति–नियंता यह समझ रहे हैं कि प्रदूषण के गंभीर हो जाने के बाद उससे निजात पाने के आधे–अधूरे कदम उठाने से समस्या का समाधान हो जाएगा तो ऐसा होने वाला नहीं है। इस पर हैरानी नहीं कि दिल्ली में ऑड–ईवन योजना पर अमल करने के बाद भी वायु प्रदूषण में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं आ सकी है। खुद सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि यह योजना प्रदूषण नियंत्रण का प्रभावी उपाय नहीं। यह मानने के अच्छे–भले कारण हैं कि सरकारें वायु प्रदूषण के मूल कारणों को समझने और उनका समुचित निवारण करने के लिए तैयार नहीं। विचित्र बात यह है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने पर तो शोर मच जाता है, लेकिन जब देश के दूसरे हिस्सों में ऐसा होता है तो अधिक से अधिक यह होता है कि इस आशय की कुछ खबरें सामने आ जाती हैं। क्या वायु प्रदूषण केवल दिल्ली के लोगों के लिए ही नुकसानदायक है? यदि नहीं तो फिर देश के दूसरे हिस्सों में फैले वायु प्रदूषण की चिंता आखिर क्यों नहीं की जाती? यह वह सवाल है, जिसका संज्ञान लिया ही जाना चाहिए। इसी के साथ यह भी समझा जाना चाहिए कि केवल आदेश–निर्देश देने, बैठकें करने और चिंता जताने से वायु प्रदूषण से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। बीते करीब एक दशक से अक्टूबर–नवंबर में वायु प्रदूषण उत्तर भारत के लिए एक आपदा जैसा साबित हो रहा है, लेकिन न तो पंजाब और हरियाणा की सरकारें पराली दहन की समस्या से निपटने के ठोस कदम उठा सकी हैं और न ही दिल्ली सरकार उन कारणों का निवारण कर सकी है, जो वायु प्रदूषण बढ़ाने का काम करते हैं। यह सरकारी तंत्र के गैर–जिम्मेदाराना रवैये की पराकाष्ठा ही है कि शहरी विकास मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति की ओर से प्रदूषण को लेकर बुलाई गई बैठक में कई विभागों के अधिकारी पहुंचे ही नहीं। सरकारी तंत्र के ऐसे रवैये के लिए एक बड़ी हद तक केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है।

कश्मीर में चिल्लई कलां की शुरुआत, पड़ रही है खून जमा देने वाली ठंड

कहा जाता है कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है, तो यहीं है, यहीं है, यही हैं। जी हाँ, धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वह है कश्मीर घाटी। आज हम आपको बताएंगे हाड़ कँपकँपा देने वाली ठंड में क्या है लोगों का हाल और बर्फबारी से लोग कितने हैं परेशान। साथ ही जानेंगे कश्मीर में शुरू हो चुके चिल्लई कलां के बारे में। कश्मीर में राजनीतिक और सामाजिक रूप से तो हालात पूरी तरह सामान्य हो चले हैं लेकिन मौसम जरा बेईमान बना हुआ है। खून जमा देने वाली ठंड के बीच वादी–ए–कश्मीर में चिल्लई कलां का आगाज हो चुका है। कश्मीर में 21 और 22 दिसम्बर की रात से भयानक सर्दी के मौसम की शुरूआत मानी जाती है। करीब 40 दिनों तक के मौसम को चिल्लई कलां कहा जाता है, इसमें अगले चालीस दिन तक बर्फबारी के साथ जमकर ठंड पड़ेगी। इस बार हुई बर्फबारी कई सालों के बाद सही समय पर हुई है। नतीजतन कुदरत का समय चक्र तो सुधारा गया लेकिन कश्मीरियों परेशानियां बढ़ गईं क्योंकि पिछले कई सालों से बर्फबारी समय पर नहीं हो रही थी। चिल्लई कलां करीब 40 दिनों तक चलता है और उसके बाद चिल्ले खुर्द और फिर चिल्ले बच्चा का मौसम आ जाता है। चिल्लई कलां के दौरान मौसम खराब रहने के कारण राजमार्ग के बार–बार बंद रहने का परिणाम यह होता है कि कश्मीरियों को चिंता इस बात की रहती है कि उन्हें खाने पीने की वस्तुओं की भारी कमी का सामना किसी भी समय करना पड़ सकता है। पहले चिल्लई कलां के शुरू होने से पहले ही कश्मीरी सब्जियों को सुखा कर तथा अन्य चीजों का भंडारण कर लेते थे। हरिसा और सूखी–सब्जियां अब सारा साल ही कश्मीर में उपलब्ध रहती हैं। चिल्ले कलां में इनकी मांग बढ़ जाती है। पहले यह सर्दियों में मिलती थी। इस समय करेला, टमाटर, शलगम, गोभी, बैंगन समेत कई अन्य सब्जियां और सूखी मछली भी बाजार में आ चुकी हैं। इन्हें स्थानीय लोग गर्मियों में सुखाकर रख लेते हैं ताकि सर्दियों में जब कश्मीर का रास्ता बंद हो जाए तो इनको पकाया जाता है। गोश्त के शौकीनों के लिए हरीसा की दुकानें पूरे कश्मीर में सजने लगी हैं। हरीसा–गोश्त, चावल व मसालों के मिश्रण से तैयार होने वाला विशेष व्यंजन है। हरिसा शरीर को अंदर से गर्म रखने के साथ कैलोरी को भी बनाए रखता है। चिल्लई कलां के दौरान कश्मीर में लोगों का पहनावा बदल जाता है। मोटे ऊनी कपड़ों के साथ फिरन पहनने वालों की तादाद बढ़ जाती है। फिरन कश्मीर का पारंपरिक पहनावा है। गर्म कपड़े से बना फिरन कई रंगों में और डिजायनों में उपलब्ध रहता है। इस दौरान फेदर जैकेट और फर जैकेट की मांग बढ़ जाती है। चिल्लई कलां के दौरान वादी में पेयजल आपूर्ति अक्सर प्रभावित होती है। पारा जमाव बिंदु के नीचे चला जाता है। दबाव से पाइप फट जाती हैं। अगर पेयजल आपूर्ति की पाइपें ठीक रहती हैं तो लोगों के घरों में नलों का पानी जमा रहता है। सुबह नौ–दस बजे के बाद ही नलों में पानी का बहाव शुरू होता है। स्थानीय लोग पाइपों को मोटे गर्म कपड़ों के नीचे या फिर घास से ढक कर रखते हैं। कई लोग बाजार में उपलब्ध थर्मोकॉल भी इस्तेमाल करते हैं।

फिलहाल तो श्रीनगर स्थित मौसम विभाग ने कहा है कि अगले तीन–चार दिनों तक जबरदस्त हिमपात की संभावना है। अगले 40 दिनों तक न्यूनतम और अधिकतम तापमान, दोनों में गिरावट आएगी। हिमपात और बारिश भी होगी। लोगों के सामने एक ही विकल्प है कि लकड़ी जला कर हाथ तापा जाये क्योंकि मौसम की मार बिजली आपूर्ति पर भी पड़ती है।

अतिश कुमार

आर्ट्स में भी है बेहतरीन भविष्य, करें इन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई

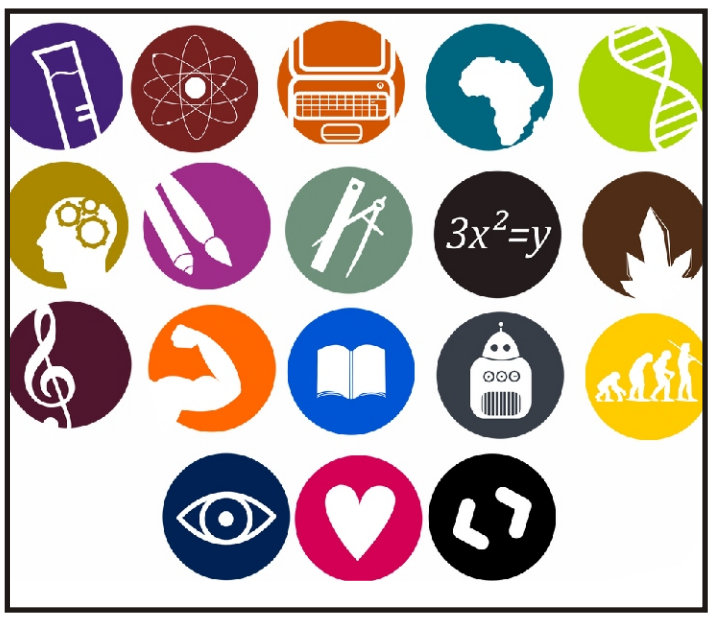

दसवीं के बाद अधिकतर छात्र साइंस स्ट्रीम की तरफ अधिक रूझान दिखाते हैं, लेकिन आर्ट्स में भी ऐसे कई सब्जेक्ट्स होते हैं, जिन्हें 11वीं व 12वीं में पढ़कर छात्र कई बेहतरीन कॅरियर विकल्प चुन सकते हैं। आर्ट्स स्ट्रीम छात्रों को कई कॅरियर विकल्प और अवसर प्रदान करता है। यह स्ट्रीम मानविकी, दृश्य कला, प्रदर्शन कला, साहित्यिक कला आदि जैसे भागों से बनी है। इस स्ट्रीम में कई तरह के अध्ययन जैसे विजुअल आर्ट्स जैसे (चित्रकला, मूर्तिकला, ड्राइंग आदि), परफार्मिंग आर्ट्स (संगीत, नृत्य, नाटक आदि), साहित्यिक कला (भाषा, साहित्य, दर्शन आदि), इतिहास, कानून, मानविकी विषय, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान आदि शामिल हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आर्ट्स स्ट्रीम में किन विषयों की पढ़ाई करते हैं और 12वीं के बाद आप अपना कॅरियर कहां–कहां देख सकते ह

सब्जेक्ट्स

सबसे पहले बात करते हैं आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़े जाने वाले विषयों के बारे में। आर्ट्स स्ट्रीम के छात्र मुख्य रूप से इन विषयों की पढ़ाई करते हैं

अंग्रेजी,इतिहास,भूगोल,राजनीति विज्ञान,अर्थशास्त्र,अन्य साहित्य विषय–हिंदी, क्षेत्रीय भाषाएं आदि

मनोविज्ञान,संगीत,गृह विज्ञान,फिजिकल एजुकेशन,पब्लिक एडमिनिस्टेशन,अंक शास्त्र,कंप्यूटर विज्ञान,फाइन आर्ट्स,सोशियोलॉजी

यहां बनाएं कॅरियर

अक्सर छात्रों व पैरेंट्स के मन में यह धारणा होती है कि आर्ट्स स्ट्रीम के छात्र एक बेहतर भविष्य नहीं बना सकते, जबकि वास्तविकता इससे बहुत अलग है। आर्ट्स स्ट्रीम के छात्रों के लिए 12वीं के बाद एक नहीं, बल्कि कॅरियर के कई बेहतरीन विकल्प मौजूद होते हैं। अगर आप भी आर्ट्स स्ट्रीम ले रहे हैं और यह जानना चाहते हैं कि आप भविष्य में किन क्षेत्रों में जा सकते हैं तो उनमें से प्रमुख हैं

एल.एल.बी,बिजनेस मैनेजमेंट,मास कम्युनिकेशन,फॉरेन लैंग्वेजेज,लिटरेचर,टूरिज्म या होटल मैनेजमेंट,एनीमेशन,इंटीरियर डिजाइनिंग,इवेंट मैनेजमेंट

इसके अलावा आजकल कुछ शॉर्ट कोर्सेज भी मौजूद हैं, जो आपको कॅरियर के बेहतर विकल्प मौजूद करता है। भले ही आप आर्ट्स स्ट्रीम के छात्र हैं, आप उन कोर्सेज को करके भी बेहतर भविष्य बना सकते हैं।

दसवीं के बाद आप किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन लेने से पहले एक बार कॅरियर काउंसलर से अवश्य मिल लें। वह आपकी रूचि व योग्यताओं के आधार पर आपको बेहतरीन सलाह दे पाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि छात्र दूसरों की देखा–देखी किसी स्ट्रीम में दाखिला ले लेते हैं और बाद में उन्हें पछतावा होता है। वैसे आजकल ऐसी कई ऑनलाइन साइट्स भी हैं, जो छात्रों की रूचि व योग्यता का आकलन करके उन्हें अच्छे करियर विकल्प के बारे में बताता है।

सत्ता के लिए गठबंधन तो हो जाते हैं लेकिन स्वार्थ हावी होते ही सरकारें गिर जाती हैं

हमारे देश की राजनीति में इस समय गठबंधन सरकारों का दौर चल रहा है। केंद्र में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार चल रही है। इसी तरह देश के कई प्रदेशों में गठबंधन की सरकारें काम कर रही हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के साथ गठबंधन कर सरकार बनाने का प्रयास कर रही है। कट्टर हिंदुवादी विचारधारा वाली पार्टी शिवसेना का कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जैसी सेकुलर पार्टियों के साथ गठबंधन करना लोगों के गले नहीं उतर पा रहा है। विशेषकर महाराष्ट्र की जनता इसे एक ऐसा बेमेल गठबंधन मान रही है जो अधिक समय तक चलने वाला नहीं होगा। शिवसेना का उदय ही हिंदुत्ववादी विचारधारा के मुद्दे पर हुआ है। ऐसे में सिर्फ सत्ता पाने के लिए कांग्रेस, एनसीपी जैसी विपरीत विचारधारा वाली पार्टियों से गठबंधन करके लंबे समय तक सरकार चला पाना शिवसेना के लिए मुश्किल ही होगा। शिवसेना के सुप्रीमो रहे स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे अपने हिंदुवादी एजेंडे के चलते ही महाराष्ट्र में शिवसेना का प्रभाव कायम करने में सफल रहे थे। 1995 से 1999 के कार्यकाल में बालासाहेब अपनी हिन्दुवादी छवि के बल पर ही महाराष्ट्र की सत्ता हासिल करने में सफल रहे थे। उस दौरान शिवसेना नेता मनोहर जोशी और नारायण राणे मुख्यमंत्री बने थे।

कभी सत्ता के लिये विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शिवसेना प्रमुख के आवास मातोश्री पर माथा टेका करते थे। मगर आज सत्ता के लिये शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का कांग्रेस, एनसीपी जैसी धुर विरोधी विचारधारा वाली पार्टियों के नेताओं के यहां चक्कर लगाना महाराष्ट्र के लोगों को नहीं भा रहा है। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में शिवसेना के 56 विधायक जिताने वाले विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता भी शिवसेना नेताओं की गतिविधियों को देखकर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लोगों का मानना है कि उन्होंने भाजपा शिवसेना गठबंधन को वोट दिए थे ना कि शिवसेना–कांग्रेस–एनसीपी के गठबंधन को।

कांग्रेस–एनसीपी गठबंधन को तो महाराष्ट्र की जनता ने चुनाव में सिरे से खारिज कर दिया था। प्रदेश की जनता द्वारा हालिया विधानसभा चुनाव में ठुकराये गये दलों का शिवसेना के साथ गठबंधन कर पिछले दरवाजे से सरकार बनाना महाराष्ट्र के मतदाताओं को अच्छा नहीं लग रहा है। महाराष्ट्र के लोगों का मानना है कि कांग्रेस–एनसीपी जैसे दलों के साथ जाकर उद्धव ठाकरे ने अपनी आगे की राजनीतिक साख खराब कर ली है। कांग्रेस एनसीपी के साथ जाने से शिवसेना के कट्टर हिंदुवादी समर्थक भी भाजपा की तरफ खिसकने लगेंगे। ऐसे में आगे चलकर शिवसेना को राजनीतिक दृष्टि से बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा जिसका शायद ठाकरे को अभी अहसास नहीं है।

लगातार दो बार 2014 व 2019 के विधानसभा चुनाव में पराजित हुये कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं को लगने लगा है कि यदि शिवसेना के साथ रहकर पिछले दरवाजे से भी सत्ता में भागीदारी मिलती है तो उसे लेने में ही उसका भला है। उन दलों के नेताओं को पता है कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है और यदि शिवसेना से अलग हटकर भारतीय जनता पार्टी आगे अकेले भी चुनाव लड़ती है तो महाराष्ट्र में आसानी से सरकार बना सकती है। ऐसे में शिवसेना को अपने साथ रख कर राजनीतिक रूप से कमजोर किया जा सकता है। इसी रणनीति के तहत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को शिवसेना से गठबंधन करने के लिए तैयार किया है।

पुराना इतिहास देखा जाए तो भारत में गठबंधन सरकारों की उम्र ज्यादा नहीं होती है। 1977 में पहली बार केंद्र में जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार बनी थी। जो आपसी विवादों के चलते ज्यादा समय तक नहीं चल पाई थी। उस समय भी कांग्रेस ने जनता पार्टी सरकार के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई व चौधरी चरण सिंह के बीच मनमुटाव पैदा करवा दिया था। कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह को समर्थन देकर प्रधानमंत्री तो बनवा दिया मगर उनकी केंद्र सरकार कुछ महिनो में ही गिर गई थी। 1980 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस भारी बहुमत से जीत गयी थी।

1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में केंद्र में एक बार फिर से जनता दल, भाजपा व वामपंथियों की गठबंधन सरकार बनी थी लेकिन आपसी खींचतान के चलते 1990 में उन्हें भी प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। इस बार भी कांग्रेस ने जनता दल के नेता चंद्रशेखर को भड़का कर वीपी सिंह के खिलाफ कर दिया था। जिस कारण वीपी सिंह को प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। फिर 1990 में कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बने जो मात्र 8 महीने के बाद लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से परास्त हो गए थे। उसके बाद 1991 में हुये चुनावों में कांग्रेस फिर से एक बार सरकार बनाने में सफल हुई थी।

1996 में भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री बने लेकिन वह सरकार कुछ दिनों में गिर गई। फिर 1996 में जनता दल के नेता एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने लेकिन 1997 में उन्हें भी अापसी खींचतान के चलते पद से इस्तीफा देना पड़ा। 1997 में इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने लेकिन उन्हें भी 1998 में पद छोड़ना पड़ा था। ऐसे ही कुछ उदाहरण विभिन्न प्रदेशों में गठबंधन सरकारों के देखे जा सकते हैं। जम्मू–कश्मीर में दो विपरीत विचारधारा वाली पार्टियों भारतीय जनता पार्टी व पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने मिलकर गठबंधन सरकार बनाई मगर आधे कार्यकाल में ही सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। इस सरकार के हटने का मूल कारण दोनों दलों की विचारधारा में टकराव को माना जाता है।

12 मई 2018 को कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस हार गई थी। वहां भारतीय जनता पार्टी 104 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। मगर कांग्रेस ने जनता दल एस से हाथ मिलाकर गठबंधन सरकार बना ली जो एक साल भी नहीं चल पाई। उससे पूर्व कर्नाटक में भाजपा और जनता दल सेक्युलर के गठबंधन की सरकार बनी थी मगर वह भी अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही सत्ता से चली गई थी।

उत्तर प्रदेश में दो विपरीत विचारधारा वाले दल भारतीय जनता पार्टी व बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई थी मगर आधे समय में ही सरकार को सत्ता से हटना पड़ा था। उसके बाद 1993 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन कर सरकार बनाई जिसमें मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने थे। मगर बीच रास्ते में ही बसपा नेता मायावती ने धोखा दे दिया और 2 जून 1995 को सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। उस समय मुलायम सिंह ने बसपा विधायकों को तोड़ कर अपनी सरकार बचा ली थी।

दिल्ली में कांग्रेस से गठबंधन कर आप ने सरकार बनाई मगर वह सरकार 49 दिन ही चल पाई थी। उसके बाद 2015 में हुये विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं जीता था। आप पार्टी के 70 में से 67 विधायक जीते। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आज भी आप की सरकार चल रही है।

गठन के 19 साल के समय में ही झारखंड में 10 सरकारें बन चुकी हैं। वहां तीन बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। झारखंड में हर बार गठबंधन सरकार बनी मगर कोई भी सरकार अपना आधा कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाई। 2014 में जरूर भाजपा ने आजसू के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई थी। मगर बाद में मुख्यमंत्री रघुबर दास ने झारखंड विकास मार्चा के चार विधायकों को भाजपा में शामिल करवा कर पूर्ण बहुमत से पांच साल सरकार चलाई है।

अतिश कुमार

Vol. 15 **No.** 11
RNI No.: DEL/BIL/2004/14598
Publisher: Ram Kailsah Gupta on behalf of Tecnia Institute of Advanced Studies, 3 PSP, Madhuban Chowk, Rohini, Delhi-85; **Printer:** Ramesh Chander Dogra; **Printed at:** Dogra Printing Press, 17/69, Jhan Singh Nagar, Anand Parbat, New Delhi-5
Editor: Rahul Mittal,Bal Krishna Mishra responsible for selection of News under PRB Act. All rights reserved.

IMPORTANT QUOTES

"I do not consider it an insult, but rather a compliment to be called an agnostic. I do not pretend to know where many ignorant men are sure -- that is all that agnosticism means."

- Clarence Darrow

*****

"Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal."

- Henry Ford

*****

"I'll sleep when I'm dead."

- Warren Zevon

*****

"There are people in the world so hungry, that God cannot appear to them except in the form of bread."

- Mahatma Gandhi

*****

Compilation:
Priya Kumari

WINNERS v/s LOOSERS Part-90

Winner sees an answer for every problem;
Loser sees a problem for every answer.

*****

Winners believe in win/win;
Loser believe for them to win, someone has to lose.

*****

Winner says "It may be difficult but it is possible";
Loser says "It may be possible but it is too difficult".

*****

Winners say "I must do something";
Losers say "Something must be done".

*****

To Be Continued In Next Issue-

Compilation:
Rahul Mittal

All Students and Faculty are welcome to give any Article, Feature & Write-up along with their Views & Feedback at: **youngstertias@gmail.com**